करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट, 41 की गई थी जान

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी, जिसमें करूर भगदड़ को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। गौरतलब है कि तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को अभिनेता विजय की रैली के दौरान अचानक भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। चीफ जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग वाली भाजपा नेता उमा आनंदन की अपील पर गौर किया। एक वकील ने पीठ को बताया, सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है, जबकि एकल न्यायाधीश ने कहा है कि वह (भगदड़ की) की जांच से संतुष्ट नहीं है।

बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

● वर्ष: 24 ● अंक: 04 ● नई दिल्ली ● बुधवार 08 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

दिल्लीवालों के लिए बड़ा मौका 'सुनियो योजना' की अवधि बढ़ी, इस दिन तक मिलेगा संपत्ति कर माफी का लाभ

नई दिल्ली। देश की राजधानी में अगर आपने अब तक अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी की खबर है. दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने नागरिकों से 'संपत्ति कर माफी योजना 2025-26' यानी 'संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो)' का लाभ उठाने की अपील की है. इस योजना के तहत पुराने बकायेदारों को ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट दी जा रही है. अब इसकी अवधि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दी गई है, जिससे नागरिकों को अपने लंबित कर का निपटान करने के लिए अतिरिक्त तीन महीने का समय मिल गया है.

बिना जुर्माने और ब्याज के कर चुकाने का मौका

'सुनियो' योजना के तहत करदाता वित्तीय वर्ष 2020-21 से पहले के बकाया संपत्ति कर पर ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं. शर्त यह है कि वे चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 और पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के लिए कर की मूल राशि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जमा करें. महापौर इकबाल सिंह ने कहा कि यह योजना नागरिकों के लिए अपनी संपत्ति कर संबंधी परेशानियों से मुक्त होने का सुनहरा अवसर है. उन्होंने सभी संपत्ति मालिकों और कब्जाधारियों से अपील की कि वे इस मौके का पूरा लाभ उठाएं और नगर निगम के साथ सहयोग करें.

अब 31 दिसंबर तक कर सकेंगे भुगतान

मूल रूप से इस योजना को 1 जून 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए लागू किया गया था. लेकिन

अब इसे तीन महीने का विस्तार दे दिया गया है और अब करदाता 31 दिसंबर 2025 तक इस योजना के माध्यम से छूट का लाभ उठा सकेंगे. विस्तारित अवधि के दौरान करदाताओं को योजना के तहत निर्धारित कर की मूल राशि पर सिर्फ 2व विलंब शुल्क देना होगा. इससे उन नागरिकों को भी राहत मिलेगी जो अब तक किसी कारणवश कर नहीं चुका पाए थे.

अब तक 1.29 लाख लोगों ने उठाया लाभ

महापौर ने बताया कि नागरिकों ने सुनियो योजना को बड़े उत्साह के साथ अपनाया है. अब तक 1.29 लाख से अधिक करदाता इस पहल का लाभ उठा चुके हैं और 519 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर जमा कर चुके हैं. इनमें से 66 हजार नए करदाता ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार संपत्ति कर भरा है. इन नए करदाताओं से ही करीब 200 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ है. महापौर ने कहा कि यह सकारात्मक रुझान इस बात का संकेत है कि लोग अब कर भुगतान को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं.

30 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ रिकॉर्ड तोड़ कर संग्रह

महापौर ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 30 सितंबर तक 11.79 लाख करदाताओं से कुल 2270 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ है. जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 9.9 लाख करदाताओं से 1736 करोड़ रुपये मिले थे. यानी इस बार कर संग्रह में 30.7व की वृद्धि और करदाताओं की संख्या में 19व की बढ़ोतरी हुई है. वित्त वर्ष 2024-25 में जहां कुल संग्रह 2132.29 करोड़ रुपये था, वहीं इस बार अब तक का आंकड़ा इसे पहले ही पार कर चुका है. महापौर ने इसे निगम और नागरिकों के बीच भरोसे का नतीजा बताया.

सुनियो योजना का लाभ उठाएं, बकाया चुकाएं : महापौर

महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा, हम सभी संपत्ति मालिकों से अपील करते हैं कि वे विस्तारित अवधि में सुनियो योजना का पूरा लाभ उठाएं और बिना किसी ब्याज या जुर्माने के अपना बकाया संपत्ति कर चुकाएं. महापौर ने उम्मीद जताई कि आने वाले महीनों में और अधिक करदाता इस योजना से जुड़ेंगे और दिल्ली को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में योगदान देंगे.

राहुल गांधी को विदेश में कौन बुलाता है? यह रहस्य है : सुधांशु त्रिवेदी का तीखा सवाल

नई दिल्ली।

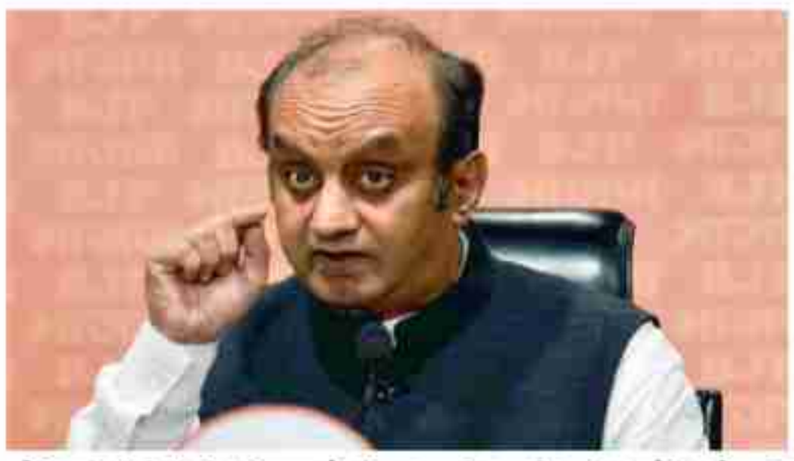

भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार को सवाल उठाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विदेशी विश्वविद्यालयों में क्यों आमंत्रित किया जाता है, जबकि उन्हें किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता। त्रिवेदी की यह टिप्पणी कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में गांधी की हालिया टिप्पणियों के बाद आई है, जहाँ उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की थी। एएनआई से बात करते हुए, भाजपा नेता ने विदेश में व्याख्यान देने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की और दावा किया कि वह भारत की छवि खराब करते हैं और देश की उपलब्धियों को नज़रअंदाज़ करते हैं। उन्होंने आगे कहा, उन्हें कौन आमंत्रित करता है, यह एक रहस्य है? त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में कई विद्वान नेता हैं। लेकिन

कोई उन्हें विदेशी विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं बुलाता, सिर्फ़ राहुल गांधी को ही क्यों बुलाता है? अगर वह इतने विद्वान हैं, तो देश का कोई भी विश्वविद्यालय उन्हें क्यों नहीं बुलाता? उन्हें कौन बुलाता है, यह एक रहस्य है। वह वहाँ जाते हैं और कुछ न कुछ कहते हैं। यह राहुल गांधी द्वारा 2 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर हमला है। गांधी ने कहा कि भारत में इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में मज़बूत क्षमताएँ हैं, इसलिए मैं देश को लेकर बहुत आशावादी हूँ। लेकिन साथ ही, इस ढाँचे में कुछ खामियाँ भी हैं जिन्हें भारत को दूर करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न परंपराओं, रीति-रिवाजों और विचारों, जिनमें धार्मिक विश्वास भी शामिल हैं, को पनपने का अवसर देती है। हालाँकि, उन्होंने आगे कहा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है, जो एक बड़ा जोखिम या ख़तरा है। गांधी ने कहा कि भारत में अनेक धर्म, परंपराएँ और भाषाएँ है - वास्तव में, यह देश मूलतः इन सभी लोगों और संस्कृतियों के बीच एक संवाद है। विभिन्न परंपराओं, धर्मों और विचारों को एक स्थान की आवश्यकता होती है, और उस स्थान को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस बीच, सुधांशु त्रिवेदी ने भी मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर किसी वस्तु को फेंककर हमला करने के प्रयास की निंदा की और कहा कि ऐसी स्थिति में भी, मुख्य न्यायाधीश ने संयम दिखाया, जिसकी सराहना की जानी चाहिए।

मोदी ने सिद्ध किया कि कैसे कोई नेतृत्व करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है : अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि कर्म योगी नरेन्द्र मोदी ने 24 साल पहले आज ही के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में संविधान की शपथ ली थी और जनसेवा की अपनी लंबी पारी के दौरान उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि जब दृष्टि राष्ट्र प्रथम और मिशन विकसित भारत हो, तो नेतृत्व करोड़ों लोगों के जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीन विधानसभा चुनावों में भाजपा को जीत दिलाने के बाद, मोदी 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार तीन राष्ट्रीय चुनाव जिता चुके हैं। शाह ने 'एक्स पर लिखा, ''राष्ट्र और जनसेवा को समर्पित 24 वर्ष! यह दिन पूरे देश के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है, जब निःस्वार्थ भाव से जनसेवा को समर्पित एक कर्मयोगी ने संविधान की शपथ लेकर लोगों की समस्याओं को अपना माना, उनका निवारण शुरू किया और ये समस्याएं इतिहास बनती चली गईं। गृह मंत्री ने कहा कि इन 24 वर्षों में, चाहे गुजरात के किसानों, महिलाओं, उद्योग और शिक्षा का कायाकल्प करना हो या फिर प्रधानमंत्री के रूप में देश की सुरक्षा, गरीबों के कल्याण और पिछड़े, दलित व जनजातीय समुदाय सहित सभी वर्गों का उत्थान करना हो, मोदी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि जब विजन 'राष्ट्रप्रथम हो और मिशन 'विकसित भारत, तब एक नेतृत्व कैसे करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। मोदी को अपने कार्यकाल के दौरान कभी चुनावी हार का सामना नहीं करना पड़ा और सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने का रिकॉर्ड उनके नाम है, जिसमें साढ़े 12 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भी शामिल है।

केजरीवाल के लिए आप की कानूनी लड़ाई सफल, लोधी एस्टेट में अब नया आशियाना

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र सरकार के साथ लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, अपने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 95 लोधी एस्टेट स्थित टाइप 7 बंगला आवंटित करवा लिया है। यह बंगला पहले भाजपा नेता और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को आवंटित किया गया था, जिन्होंने पंजाब से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब केजरीवाल ने 2024 में सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने अक्टूबर 2024 में सिविल लाइंस में 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग स्थित आवास खाली कर दिया। कई राज्यों के विपरीत, दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने का प्रावधान नहीं है, जिससे आप को अपने नेता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है।

आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल, जो वर्तमान में 5 फ़िरोज़शाह रोड (टाइप VII) के आवंटी हैं, ने केजरीवाल से अस्थायी रूप से स्थानांतरित होने का आग्रह किया, जबकि पार्टी ने कानूनी कार्यवाही शुरू करते हुए मांग की कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (रूण) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) संपदा निदेशालय को राष्ट्रीय संयोजक के लिए एक आधिकारिक आवास की पहचान और आवंटन करने का निर्देश दें। आप ने तर्क दिया कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख होने के नाते, केजरीवाल टाइप 8 बंगले के पात्र हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, केंद्रीय एजेंसियों ने अंततः इस उद्देश्य के लिए 95 लोधी एस्टेट की पहचान की। केजरीवाल को आवंटित टाइप 7 बंगले में चार शयनकक्ष, एक हॉल, एक प्रतीक्षालय और एक भोजन कक्ष है। इसमें दो लॉन हैं, जिनमें से एक छोटा है। वर्तमान कैंप कार्यालय में दो कमरे हैं, जबकि स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारी लगभग एक दशक से यहीं रह रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोमवार को बंगले का दौरा किया। उम्मीद है कि सामान्य नवीनीकरण और संशोधन पूरा होने के बाद परिवार इसमें शिफ्ट हो जाएगा। यह आवंटन शीशमहल विवाद की यादों के बीच हुआ है, जब केजरीवाल को दिल्ली में आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश, लुढ़का तापमान और ऑरेंज अलर्ट पर यूपी और दिल्ली के ये जिले

नई दिल्ली।

दिल्ली-एनसीआर में आज (मंगलवार) तड़के से ही झमाझम बारिश हो रही है। इससे पहले सोमवार को भी एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने गुलाबी ठंड का अहसास करा दिया है। वहीं, दो दिन से बारिश होने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को अभी से ठंड का भी अहसास होने लगा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को कई शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। बताया गया कि दिल्ली के सभी जिले ऑरेंज अलर्ट पर हैं, जबकि यूपी के नोएडा और गाजियाबाद भी ऑरेंज अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उधर, आज सुबह से ही तेज बारिश होने से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव भी हो गया है। जलभराव होने से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज लोगों को ऑफिस पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 7.7 डिग्री कम 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह इस सीजन का ही नहीं बल्कि 2022 के बाद तीन साल में अक्टूबर माह का सबसे कम अधिकतम तापमान है। इससे पहले 2022 में आठ अक्टूबर के दिन यह 23.4 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री कम 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का स्तर 100 से 78 प्रतिशत जबकि शाम साढ़े पांच बजे तक वर्षा 3.4 मिमी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को भी दिल्ली में सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। यादातर जगह हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होगी। गरज वाले बादल बनने, बिजली चमकने और 30 से 50 किमी प्रति घंटे की दर से तेज झोंकेदार हवा चलने की भी संभावना है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश 30 और 20 डिग्री रह सकता है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का साझा दुख

अनिल जैन

केंद्र सरकार की हठधर्मिता के चलते सीमावर्ती केंद्र शासित लद्दाख में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एपेक्स बॉडी लेह (एबीएल) के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाकरुक ने केंद्र के साथ बातचीत करने से इनकार करते हुए कहा है, हमें राष्ट्र विरोधी कहना हमारा और हमारी देशभक्ति का अपमान है। हम बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं कर सकते।'' उन्होंने बातचीत से पहले राष्ट्र-विरोधी का आरोप वापस लेने और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित सभी गिरफ्तार लद्दाखियों की रिहाई की मांग की है। लाकरुक ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा, लेह के लोग अनुच्छेद 370 को अभिशाप समझते थे, क्योंकि यह लद्दाख के लोगों के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने की राह में रुकावट था। लेकिन अब हम मानते हैं कि इस अनुच्छेद ने 70 साल तक हमें संरक्षण दिया। इसके ना होने के बाद ये सारा इलाका बाकी देश के लोगों के लिए खुल गया है और स्थानीय लोगों की सुरक्षा घट गई है।'' ऐसी बातें लोग सामान्यत: घोर निराशा की हालत में कहते हैं। अब सवाल केंद्र से है कि अगस्त 2019 में लद्दाख के लोगों में जो उम्मीदें पैदा हुईं, उन्हें पूरा क्यों नहीं किया गया? हकीकत यह है कि केंद्र की समझ और लद्दाख-वासियों के एहसास में गहरी खाई बन चुकी है। 24 सितंबर को हिंसक घटनाओं ने इसे और गहरा दिया है। यह मौका है कि केंद्र सरकार लद्दाख-वासियों के मन की बात को संजीदगी से सुने। लद्दाख सीमाई इलाका है, जिस पर चीन की नजर रहती है। वहां के लोगों में असंतोष गहराना भारत के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार-बार कहते हैं कि सही समय आने पर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का वह दावा ही सही साबित होता दिख रहा है। सत्यपाल मलिक ने अपनी मृत्यु से कुछ दिनों पहले अपने कुछ करीबी मित्रों को बताया था कि जम्मू-कश्मीर को मोदी के प्रधानमंत्री रहते कभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उनके दावे के मुताबिक मोदी ने खुद उन्हें कहा था कि मेरे रहते हुए जम्मू-कश्मीर को कभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है।'' अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी हुए और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बने पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। अब लद्दाख की ताजा घटनाओं से तो हालात और ज्यादा बदल गए हैं। गौरतलब है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ तो बड़ी हिंसा हुई और चार लोग मारे गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कहा कि लद्दाख के आंदोलन को देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में क्या चल रहा होगा। जाहिर है जम्मू कश्मीर में यहां खदबदाहट है। लेकिन लद्दाख के घटनाक्रम से सुरक्षा की चिंताएं बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार लद्दाख में विदेशी ताकतों खास कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के सक्रिय होने की बात कह रही है। जाहिर है कि इसी बहाने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को टाला जाएगा। असम में अगले साल अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी के चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हारी है। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अकेले दम पर बड़ा बहुमत हासिल किया। 40 सीटों के बीटीसी चुनाव में हागरामा महलारी की पार्टी बीपीएफ को 28 सीटें मिली हैं। गौरतलब है कि पहले भाजपा का बीपीएफ के साथ गठबंधन था। लेकिन बाद में उसकी विरोधी पार्टी यूपीपीएल के साथ मिल कर भाजपा ने बीपीएफ को निपटा दिया था। लेकिन पांच साल के बाद बीपीएफ ने वापसी कर ली है। इसका बड़ा नुकसान भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी को हुआ है। महलारी खुद दो सीटों से लड़े थे, जिसमें से एक सीट पर जीते हैं और यूपीपीएल के नेता प्रमोद बोडो भी दो सीटों से लड़े थे और एक ही सीट पर जीते हैं। इस मामले में दोनों बराबरी पर हैं लेकिन महलारी की पार्टी ने भाजपा और यूपीपीएल दोनों को जमीन दिखा दी है। अब विधानसभा चुनाव में नए समीकरण बनने की जरूरत पैदा हो गई है। पिछले यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में बीपीएफ ने कांग्रेस के बजाए गठबंधन महाजोत के साथ चुनाव लड़ा था। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ भी महाजोत का हिस्सा थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सब अलग हो गए थे लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगले साल के चुनाव में एक बार फिर विपक्ष का बड़ा गठबंधन बनेगा। कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो अक्सर जाने-अनजाने ऐसे बयान देते रहते हैं जो कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा करते हैं। इस सिलसिले में मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा आदि नेताओं के बयानों को याद किया जा सकता है। अब कतार में पी. चिदंबरम भी शामिल हो गए हैं। चिदंबरम काफी पढ़े लिखे नेता हैं और जनाधार न होने के बावजूद वर्षों तक केंद्र सरकार में अहम मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से भी वे अछूते नहीं रहे हैं। इस सिलसिले में वे और उनके बेटे कार्ति दोनों जेल में भी रह चुके हैं। अब भी उनके पूरे परिवार पर केंद्रीय एजेंसियों की तलवार लटक रही है। इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने पिता, पुत्र दोनों को एडजस्ट किया है। पी. चिदंबरम राज्यसभा में हैं तो उनके बेटे को उनकी पारंपरिक शिवगंगा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया था, जहां गठबंधन के बूते वे जीत गए। पी. चिदंबरम ने कांग्रेस को बहुत गहरा घाव दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका के दबाव में कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। उनके इस बयान के बाद हंगामा मचा जो कि स्वाभाविक था। भाजपा इसको लेकर कांग्रेस को घेर रही है और कांग्रेस के लिए इसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल यह समझना मुश्किल नहीं है कि भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमों का सामना कर रहे चिदंबरम ने यह बयान क्यों दिया होगा।

वसुंधरा की सक्रियता से क्या बदलेगा?

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता के किस्से चर्चा में हैं। वे अचानक राजनीतिक बियाबान से निकल कर सत्ता के गलियों में चहलकदमी करने लगी हैं। सवाल है कि इससे क्या बदलेगा? उनकी दो इच्छा है। पहली राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना और दूसरी अपने बेटे दुष्यंत सिंह को केंद्र में मंत्री बनवाना, जो लगातार चार बार से लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। वसुंधरा राजे की उम्र 72 साल है और वे राजस्थान विधानसभा की सदस्य भी हैं। वे इशारों में खुद के राजनीतिक वनवास में होने की बात भी कह रही हैं। वे निःसंदेह राजस्थान में भाजपा की सबसे बड़ी और प्रभावशाली नेता हैं और शायद इसी वजह से पार्टी के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें हाशिए पर डाल रखा है। इसलिए सवाल है कि क्या उनका वनवास खत्म होगा? अफवाहबाज मीडिया कुछ दिन पहले उन्हें उप राष्ट्रपति बनवा रहा था। फिर कहा गया कि वे भाजपा की पहली महिला अध्यक्ष हो सकती हैं। लेकिन यह भी संभव नहीं लगता है। संसद के मानसून सत्र के दौरान वसुंधरा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।

इसके अलावा जोधपुर में जब संघ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे तो उनसे भी वसुंधरा की आधे घंटे की मुलाकात हुई।

कहा जा रहा है कि इतनी सक्रियता से राजस्थान मंत्रिमंडल में उनके कुछ करीबी नेताओं को जगह मिल जाएगी। लेकिन वसुंधरा की सक्रियता निश्चित रूप से इतने भर के लिए नहीं है।

सम्पादकीय...

भगदड़ : भारत क्यों बार-बार विफल हो रहा है ?

भारत, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां धार्मिक उत्सव, राजनीतिक रैलियां और सांस्कृतिक आयोजन में लाखों-करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं। वहां भीड़ प्रबंधन की विफलता एक बार फिर से राष्ट्रीय शर्म का कारण बन रही है। हाल के वर्षों में हुई कई भयानक घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि प्रशासनिक लापरवाही, अपर्याप्त योजना और बुनियादी ढांचे की कमी कैसे निर्दोष लोगों की जान ले रही है। सितंबर 2025 में तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-नेता विजय की राजनीतिक रैली में 41 लोगों की मौत हो गई, जब देरी से पहुंचे काफिले को देखने के लिए लोग सड़क पर उमड़ पड़े। भगदड़ के हादसों की सूची बहुत लंबी है लेकिन यहां सवाल उठता है कि एक के बाद एक हादसों से हमने क्या सीखा? क्या ऐसे हादसे कभी कम होंगे? 2024 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। यह घटना कार्यक्रम समाप्ति के समय भीड़ के बहाव के कारण हुई, जब लोग बाबा के चरण छूने या उनकी चरण रज लेने के लिए उमड़ पड़े। इसी तरह, 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ मेले में 'मौनी अमावस्या' के दिन पवित्र नदी में स्नान के दौरान हुई भगदड़ ने 30 लोगों की जान ले ली और 60 से अधिक घायल हो गए। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि भारत अपनी जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बार-बार असफल हो रहा है। इन घटनाओं पर शासन और प्रशासन इतना गंभीर क्यों नहीं दिखाई देता? हाल के वर्षों में भारत में भगदड़ की घटनाएं एक चक्रव्यूह की तरह घूम रही हैं। 2024 के दिसंबर में हैदराबाद के संध्या थियेटर में 'पुष्पा 2' फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। 2025 की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शन के टोकन वितरण के समय छह भक्तों की मौत हो गई, जब हजारों लोग टोकन के लिए उमड़ पड़े। फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज पर हुई भगदड़ ने कई जानें लीं। बेंगलुरु में क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी)की आईपीएल विजय परेड के दौरान 11 लोगों की मौत हुई, जहां प्रशासन ने भीड़ का अनुमान लगाने में चूक की। बिहार के बाबा सिद्धनाथ मंदिर में अगस्त 2024 की भगदड़ में सात मौतें हुईं। ये घटनाएं धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों में ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशनों और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी हो रही हैं। 1954 से 2012 तक भारत में 79% भगदड़ें धार्मिक आयोजनों के दौरान हुईं, जो आज भी जारी है। इन विफलताओं के पीछे कई गहरे कारण हैं। सबसे प्रमुख है आमंत्रित भीड़ का होना और अपर्याप्त प्रबंधन। आयोजक अक्सर अनुमानित संख्या से अधिक लोगों को आने की अनुमति मांग करते हैं, जबकि निकास मार्ग संकरे और अपर्याप्त होते हैं। अनुमति देने वाले विभाग भी किन्हीं कारणों के चलते सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों पर जोर नहीं देते। हाथरस में अस्थायी टेंट में पर्याप्त निकास न होने से भगदड़ बढ़ी। अफवाहें, जैसे आग लगने या ढांचा गिरने की, घबराहट और भगदड़ पैदा करती हैं। बुनियादी ढांचे की कमी, पुरानी इमारतों, संकरी सड़कों और पहाड़ी इलाकों में तो समझी जा सकती है। वहीं सुरक्षा कर्मियों की कमी और अप्रशिक्षित होना एक और समस्या है। महाकुंभ में वीआईपी व्यवस्थाओं पर फोकस से आम भक्तों की उपेक्षा हो जाती है। राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों में भावनाओं का उफान भीड़ को अनियंत्रित बनाता है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन में पुलिस, आयोजकों और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय की कमी घटनाओं को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशा-निर्देशों का पालन न होना एक बड़ी लापरवाही है। ये सभी कारक मिलकर भारत को बार-बार विफल कर रहे हैं, जहां जनता की जानें सस्ती साबित हो रही हैं। ये भगदड़ें केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, इनका मानवीय और सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा है। परिवार टूट जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। फिर सवाल उठता है कि इनसे कैसे बचा जाए? प्रबंधन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। सबसे पहले, पूर्व नियोजन जरूरी है। आयोजकों को अनुमति देते समय क्षमता का सख्त आंकलन हो और अधिकतम संख्या तय की जाए। बुनियादी ढांचे में सुधार लाएं, चौड़े निकास, आपातकालीन मार्ग और मजबूत संरचनाएं। एनडीएमए के अनुसार सीसीटीवी, ड्रोन और एआई का उपयोग भीड़ निगरानी के लिए किया जाए, जैसा कुंभ में प्रयास हुआ। सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाएं और उन्हें विशेष प्रशिक्षण दें। अफवाहों पर नियंत्रण के लिए 'रियल टाइम' संचार प्रणाली लगाएं। अंतर-एजेंसी समन्वय मजबूत करें-पुलिस, आयोजक और नागरिक प्रशासन एक साथ काम करें। कानूनी सख्ती लाएं, लापरवाह आयोजकों पर कड़ी सजा और मुआवजा सुनिश्चित करें। जन जागरूकता अभियान चलाएं, जहां लोग भीड़ में धैर्य रखें और सहयोग करें। भारत को एक के बाद एक हुई इन विफलताओं से सबक लेना होगा। सरकार, आयोजक और नागरिकों की संयुक्त जिम्मेदारी से ही भविष्य की त्रासदियां रोकी जा सकती हैं। अन्यथा, ये घटनाएं जारी रहेंगी और देश अपनी जनता को बचाने में असमर्थ साबित होगा। समय आ गया है कि प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया जाए, जैसा कि कहा जाता है कि, 'प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर'। केवल तभी हम एक सुरक्षित भारत का निर्माण कर पाएंगे।

दार्जिलिंग की आपदा

पश्चिम बंगाल के पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही मच गई है जिसने 23 लोगों की जान ले ली। सैकड़ों घर तबाह हो गए, सड़कें बह गईं। इसके चलते सिक्किम राज्य से भी सम्पर्क टूट गया। भूस्खलन से दार्जिलिंग के पास जलपाईगुड़ी जिला भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बालासोन नदी पर बना दूधिया पुल भी टूट गया जिससे सिलीगुड़ी और मिरिक का सम्पर्क भी टूट गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए। इसी बीच भूटान ने वांगचू नदी में जलस्तर की वृद्धि के कारण उत्तरी बंगाल में बाढ़ की चेतावनी दे दी है। उत्तराखंड और हिमाचल की प्राकृतिक आपदाओं के बाद हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र दार्जिलिंग में भूस्खलन यद्यपि एक सामान्य प्राकृतिक घटना है लेकिन यह आपदा हमें सतर्क कर रही है कि लोकप्रिय हिल स्टेशन में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो अपनी खूबसूरती और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए मशहूर दार्जिलिंग अतीत में कई प्राकृतिक आपदाओं का शिकार रहा है। उपलब्ध रिकॉर्ड बताते हैं कि 1899, 1934, 1950, 1968, 1975, 1980, 1991 और हाल ही में 2011 और 2015 में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुए थे। 1968 में अक्तूबर में ही विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिसमें एक हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे। गैर-लाभकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट द्वारा प्रकाशित पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट, 1991 में कहा गया है कि 1902-1978 के दौरान तीस्ता घाटी में बादल फटने की नौ घटनाएं हुईं। देशभर में आपदा की व्यापकता ने पर्यावरणविदों और शोधकर्ताओं को चिन्ता में डाल दिया है। पहाड़ों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है और अपनी प्रकृति में युवा है। यदि इसकी उचित देखभाल नहीं की गई तो दार्जिलिंग में उत्तराखंड और हिमाचल जैसी प्रलय आ सकती है। जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी, पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या, दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों यहां तक कि सिक्किम की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डाल रही है। पूर्वी हिमालय के समग्र पर्यावरणीय क्षरण से पहाड़ नंगे और बदसूरत हो चुके हैं। लगातार वनों की कटाई से मिट्टी के कटाव की समस्या बढ़ गई है।

झरनों के सूखने और पानी के स्तर में बदलाव से भी समस्या बढ़ गई है। जिस तरह से इमारतों का प्रसार हुआ है और पहाड़ी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतें बनती जा रही हैं जिनमें उचित जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। पहाड़ क्षेत्र भी भीड़भाड़ वाले होते जा रहे हैं। पुराना आकर्षण खत्म हो गया है। पर्यटकों को ले जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण बढ़ चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा प्रकाशित भारत के भूस्खलन एटलस 2023 में, दार्जिलिंग को 147 जिलों में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में 35वें स्थान पर रखा गया था। कलिम्पोंग के कर्नल प्रफुल राव के नेतृत्व वाले सेव द हिल्स सहित कई स्थानीय गैर सरकारी संगठन सोशल मीडिया पर तथा ठोस बहसों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से इन खतरों को उजागर कर रहे हैं। सिक्किम में अक्तूबर 2023 में ल्होनक झील के टूटने से उत्पन्न होने वाली ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) के बारे में सिक्किम मानव विकास रिपोर्ट 2001 में बहुत जोरदार चेतावनी दी गई थी। इस जीएलओएफ ने न केवल कई लोगों की जान ले ली, बल्कि 1200 मेगावाट की चुंगथांग जल विद्युत परियोजना को बहा ले गया, कई सार्वजनिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया और अनुमानित 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की क्षति हुई जो 2022-23 के सिक्किम के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60 प्रतिशत है।

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के निचले तटवर्ती क्षेत्रों तथा बंगलादेश में इसके कारण हुई भारी तबाही का अभी तक कोई हिसाब नहीं है। भारी वर्षा के साथ लम्बी अवधि के दौरान जल भराव बढ़ जाता है जिससे संवेदनशील इलाकों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ता है। ग्रामीण और ऊंची पहाड़ियों में लोग ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पेड़ों की अवैध कटाई लगातार जारी है। ब्रिटिश काल में भवन निर्माण मानदंडों और दिशा-निर्देश पूरी तरह से त्याग दिए गए। पहाड़ों को बचाने के लिए कोई कारगर योजना लागू ही नहीं की गई। तत्कालिक आर्थिक लाभ और तीव्र विकास ने पर्यावरण को संकट में डाल दिया है। प्राकृति मनुष्य के हाथों वर्षों से चली रही खामोश बदनामी और निरंतर अनादर का बदला लेने के लिए पलटवार करती दिखाई दे रही है। जितना मानव ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया है। सरकारों को चाहिए कि कारणों की पहचान कर उनके निवारण के निष्कर्षों से पता चलता है कि न तो भूस्खलन को रोकना संभव है न ही इसके नुकसान को पूरी तरह से समाप्त करना लेकिन कुछ बुनियादी उपायों और सार्वजनिक जागरूकता के साथ काम किया जाए तो नुकसान की संभावना को सीमित किया जा सकता है।

दलित जज पर हमला- ब्राह्मणवाद और असमानता की हकीकत!

अचरज की बात यह है कि यह जज दलित हैं, और खुद को सनातनी कहने वाले वकील ने उनके स्थान और सम्मान का कोई ख्याल नहीं रखा। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम की परछाई है जिसमें आज भी दलित, चाहे वे जज हों, IAS हों, पुलिस अफसर हों या किसी बड़े पद पर हों, उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। हमारे देश का इतिहास गवाह है। बाबा साहेब अंबेडकर ने सदियों के अत्याचारों को देखकर भारत का संविधान बनाया कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलें। लेकिन आज, स्वयं को सनातनी कहने वाले लोग संविधान को नकार कर दलितों पर अत्याचार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, और किसी भी हद तक जाने से भी नहीं डरते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि भारत के संविधान और न्यायपालिका पर हमला है, जो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है यह घटना याद दिलाती है कि केवल अदालत में ही नहीं, बल्कि राजनीति, शिक्षा, सिविल सर्विस, और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में दलितों को बराबरी का सम्मान नहीं मिलता। जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंदिर में प्रवेश से रोका गया था नई संसद की उद्घाटन समारोह में भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया गया यह एक भयानक सच्चाई है जब भारत के प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज इस नफरत से सुरक्षित नहीं हैं, तो कल यह किसी सामान्य दलित के साथ कितनी भयावह स्थिति ले सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है स्वयं को सनातनी कहकर हिन्दू राष्ट्र का दावा करने वालों का इतिहास हमें बताता है कि किस तरह जाति को बहाना बनाकर दलितों पर अत्याचार किए गए। आज भी हम कई उदाहरण देख रहे हैं, केवल रूप बदल गया है, पर तीव्रता वही है यह घटना केवल एक जज पर हमला नहीं, बल्कि हर दलित, हर पीड़ित के लिए चेतावनी है कि सामाजिक न्याय और मानव सम्मान अभी भी खतरे में है। हमें अपने आप से यह सवाल करना होगा- हम इस अत्याचार को रोकने के लिए कब और कैसे खड़े होंगे? बाबा साहेब अंबेडकर ने हमारे लिए संविधान बनाया, न्याय का मार्ग खोला, लेकिन आज हमें यह देखना पड़ रहा है कि संविधान के रक्षक स्वयं दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ असमान व्यवहार कर रहे हैं। अगर आज हम केवल देखते रहेंगे, तो कल इसका परिणाम बेहद भयावह होगा यहीं पर हमें अंबेडकर साहेब की कुछ बातें याद आ रही हैं बाबा साहेब ने अपने दलित भाइयों और बहनों से बार-बार कहा अपनी इज्जत के लिए खड़े होना सीखो, अत्याचार को सहन मत करो, और सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाओ जाति-बन्धन से मुक्ति हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है।

कफ सिरप विवाद-सर्दी खांसी की दवा से पैदा हुआ राष्ट्रीय अलार्म और अंतरराष्ट्रीय चिंता- स्वास्थ्य सुरक्षा, नियमन और जवाबदेही पर व्यापक विश्लेषण

भारत में पिछले कुछ समय से दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में एक कफ सिरप को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है,उसने न केवल भारत के कई राज्यों को कार्रवाई के लिए मजबूर किया है, बल्कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय भी बन गया है।तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राजस्थान और केरल जैसे राज्यों ने इस सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि गुजरात समेत कई अन्य राज्यों ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह पूरा प्रकरण भारत के औषधि नियंत्रण ढांचे,दवा उद्योग की पारदर्शिता,और बच्चों की सेहत से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, कफ सिरप विवाद- खांसी की दवा से पैदा हुआ राष्ट्रीय अलार्म और अंतरराष्ट्रीय चिंता- स्वास्थ्य सुरक्षा, नियमन और जवाबदेही पर व्यापक विश्लेषण। साथियों बात अगर हम एक कफ सिरप विवाद की पृष्ठभूमि, प्रतिबन्ध तथा एक साधारण खांसी की दवा से कैसे मचा तहलका इसको समझने की करें तो एक कफ सिरप एक ओवर- द-काउंटर (ओटीसी) दवा के रूप में बाजार में बेची जा रही थी। यह सामान्य तौर पर सर्दी, खांसी और जुकाम से राहत के लिए दी जाती थी। इस सिरप का निर्माण कई छोटी फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा किया जा रहा था, और यह विभिन्न ब्रांड नामों से ग्रामीण और शहरी बाजारों में उपलब्ध थी। विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ राज्यों में स्वास्थ्य विभागों को रिपोर्ट मिली कि बच्चों को यह सिरप देने के बाद उल्टी, सांस लेने में तकलीफ और लिवर फेल्योर जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं।मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद महाराष्ट्र एफडीए ने कोल्ड्रिफ सिरप (बैच एसआर -13) की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है।यूपी ड्रग्स विभाग ने मेडिकल स्टोर में रखे गए कफ सिरप के जांच के आदेश दे दिए हैं।इस सिरप से अब तक एमपी में 16 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत होने की जानकारी मीडिया में आ रही है,इसके बाद जब प्रयोगशाला में जांच की गई, तो पाया गया कि इस दवा में डायएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे अत्यंत जहरीले रासायनिक तत्व मौजूद हैं।इन दोनों रसायनों का उपयोग सामान्यतः एंटीफ्रीज के रूप में औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, और इनका मानव शरीर में प्रवेश घातक साबित हो सकता है। यही वह बिंदु था जिसने उस कफ सिरप को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद के केंद्र में ला दिया।किन राज्यों ने की कार्रवाई-तमिलनाडु से केरल तक बैन की लहर-इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई राज्यों ने तुरंत कदम उठाए।(1)तमिलनाडु सरकार ने सबसे पहले इस सिरप की बिक्री और वितरण पर रोक लगाने की घोषणा की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों में विषाक्तता के कुछ मामले देखने के बाद एहतियाती कदम उठाना जरूरी था। (2) मध्य प्रदेश ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को आदेश दिए कि वे इस सिरप के सभी बैचों को बाजार से वापस लें और जांच रिपोर्ट आने तक इसकी बिक्री बंद रखें।(3)महाराष्ट्र सरकार ने इसी दिशा में कदम उठाते हुए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी किया कि वे इस सिरप को अपने स्टॉक से हटा दें।(4)केरल ने भी इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और केंद्र से यह स्पष्ट करने की मांग की कि आखिर इस दवा को ड्रग कंट्रोलअथॉरिटी की मंजूरी कैसे मिली।(5)गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों ने जांच शुरू कर दी है कि कहीं बाजार में बिक रही अन्य कफ सिरप में भी ऐसे ही हानिकारक तत्व तो नहीं हैं। साथियों बात अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, बच्चों को 'कफ सिरप' देने से पहले सोचें सौ बार इसको समझने की करें तो,केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्रीय एडवाइजरी जारी की है।इस एडवाइजरी में स्पष्ट कहा गया है कि -दो साल से छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार का कफ सिरप बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए।-मंत्रालय ने डॉक्टरों, पैरेंट्स और फार्मासिस्टों से आग्रह किया है कि वे बच्चों के लिए ओटीसी (ओवर-द-काउंटर) दवाओं का उपयोग सोच- समझकर करें, क्योंकि कई बार इन दवाओं में मौजूद रासायनिक घटक बच्चे के शरीर के मेटाबॉलिज्म के अनुरूप नहीं होते।यह सलाह ऐसे समय पर आई है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले भी भारत निर्मित कफ सिरपों से जुड़े मौतों पर चिंता जताई थी।2022-23 में गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में कई बच्चों की मौत भारत में बनी कुछ खांसी की दवाओं के कारण हुई थी। यह नया मामला उसी चिंता को फिर से ताजा कर देता है। साथियों बात अगर हमखतरनाक तत्व,डायएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की घातकता को समझने की करें तो,अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह तत्व इतना खतरनाक क्यों है।डायएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल दोनों ही औद्योगिक उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। ये तरल पदार्थ गंधहीन, रंगहीन और मीठे स्वाद वाले होते हैं, जिसके कारण कई बार सिरप में सॉल्वेंट के रूप में गलती से या लापरवाही से मिल जाते हैं।लेकिन जब ये शरीर में जाते हैं, तो लिवर और किडनी इन्हें प्रोसेस नहीं कर पाती, और इनके टूटने से बनने वाले रासायनिक यौगिक शरीर के नर्वस सिस्टम, किडनी और ब्रेन को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं।डब्ल्यूएचओ की रिपोर्टों के अनुसार,डीईजी से हुई विषाक्तता किडनी फेल्योर, दृष्टि हानि, सांस लेने में रुकावट और अंततः मृत्यु तक का कारण बन सकती है।भारत में यह कोई पहली घटना नहीं है,1998 में दिल्ली में, और 2020 में जम्मू-कश्मीर में भी डीईजी विषाक्तता से बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। साथियों बात अगर हम दवा नियामक प्रणाली पर सवाल, जांच, जिम्मेदारी और जवाबदेही को समझने की करें तो, कफ सिरप प्रकरण ने भारत की ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।भारत दुनियाँ का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा निर्माता है और 200 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात करता है।

ऐसे में बार-बार भारतीय दवाओं पर अंतरराष्ट्रीय स्तरपरसवाल उठना देश की छवि को भी प्रभावित करता है।यह मामला यह भी दिखाता है कि-(1)राज्य स्तरीय ड्रग टेस्टिंग लैब्स अक्सर ओवरलोड रहती हैं।(2)सैंपलिंग और क्वालिटी कंट्रोल में असमानता है। (3) कई बार लाइसेंसिंग अथॉरिटी स्थानीय राजनीतिक या औद्योगिक दबावों के कारण उदार रवैया अपनाती है।ऐसी स्थितियों में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन की भूमिका और मजबूत करने की जरूरत है ताकि किसी भी बैच को बाजार में आने से पहले अनिवार्य रूप से कफ सिरप लॉजिकल टेस्टिंग से गुजारा जा सके। साथियों बात अगर हम जनता में भय और भ्रम की स्थिति को समझने की करें तो सोशल मीडिया के द्वारा आग और हवा से भी तेज गति से कफ सिरप के संबंध में स्वास्थ्य सुरक्षा का संकट फैलने की करें तो, सिरप पर बैन की खबरें फैलीं, लोगों में व्यापक भय और भ्रम फैल गया। कई जगह माता-पिता ने घरों में रखी सभी कफ सिरप की बोतलें फेंक दीं। मेडिकल दुकानों ने बिक्री बंद कर दी।डॉक्टरों के पास बड़ी संख्या में लोग यह पूछने पहुंचे कि कौन सी खांसी की दवा सुरक्षित है।यह परिदृश्य बताता है कि भारत में स्वास्थ्य संचार (हेल्थ कम्यूनिकेशन) की प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत है।सरकार को ऐसे मामलों में तत्काल हेल्पलाइन, वेबसाइट और सूचना अभियान चलाने चाहिए, ताकि अफवाहों से बचा जा सके और सहीजानकारी जनता तक पहुँच सके। साथियों बात कर हमअंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण,विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक नियामक एजेंसियों की भूमिका को समझने की करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के दवा नियामक निकायों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा यूएस एफडीए यूके, एमएचआरए और यूरोपीय औषधि एजेंसी जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी भारत में बने फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स पर नजर रखे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने बयान में कहा, -बच्चों की दवाओं में कोई भी ग्लाइकॉल बेस्ड टॉक्सिन की मौजूदगी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।-इस मामले का असर भारत की फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है,विदेशी खरीदार भारतीय दवाओं की क्वालिटी सर्टिफिकेशन को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने लगे हैं, जिससे भारत की दवा कंपनियों की विश्वसनीयता और बाजार हिस्सेदारी पर असर पड़ सकता है। साथियों बात अगर हम कानूनी और प्रशासनिककार्यवाही तथा क्या दोषियों को सजा मिलेगी? को समझने की करें तो, स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित निर्माताओं,डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर जांच में यह सिद्ध होता है कि इन कंपनियों ने जानबूझकर या लापरवाही से खतरनाक तत्वों का प्रयोग किया है, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट,1940 के तहत उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। साथियों बात अगर हमवैकल्पिक समाधान व बच्चों के लिए सुरक्षित दवा नीति की जरूरत की करें तो,भारत को तत्काल एक नेशनल पेडिअट्रिक ड्रग सेफ्टी पॉलिसी की आवश्यकता है। इस नीति में शामिल होना चाहिए - (1) बच्चों की उम्र के अनुसार दवाओं की सुरक्षित डोजिंग गाइडलाइन(2)टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए अलग मानक (3) फार्मासिस्ट और डॉक्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (4) ओटीसी (बिना पर्ची की दवा) बिक्री पर नियंत्रण (5) डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम ताकि हर दवा के बैच की जानकारी सार्वजनिक हो सके।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने बन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैन्टलवान एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

ग्राम प्रधानों की शिकायतों पर हुआ मंथन

मुरादाबाद। मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में विकास भवन में जिले के ग्राम प्रधानों की शिकायतों की जांच से संबंधित जांच अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि 14 ग्राम प्रधानों की जांच से संबंधित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी नामित जांच अधिकारी प्रकरणों की जांच करके आख्या अनिवार्य रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उपयुक्त श्रम रोजगार, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी मौजूद रहे।

महर्षि वाल्मीकि के आदर्श आज भी प्रासंगिक: रामवीर सिंह

मुरादाबाद।

मूंढापांडे ब्लॉक के ग्राम जैतपुर विसाहट, खाई खेड़ा और दलपतपुर में महर्षि भगवान बाल्मीकि की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रमों में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ग्राम दलपतपुर में बाल्मीकि मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में बाल्मीकि समाज ने माला एवं पगड़ी पहनाकर विधायक का स्वागत किया। विधायक कुंदरकी ठाकुर रामवीर सिंह ने महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को आज भी प्रासंगिक बताया। रामायण के माध्यम से समाज को आदर्शों, मर्यादा और मानवीयता का मार्ग दिखाया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि समाज का हर वर्ग बिना किसी भेदभाव के एक साथ आगे बढ़े और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। भगवान महर्षि वाल्मीकि ने हमें शिक्षा, संस्कार और अनुशासन की जो प्रेरणा दी है, हमें उससे प्रेरित होकर समाज को आगे ले जाना होगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा को अपनाना होगा। हमें ऐसी भावना को पैदा करना है, जिसमें सभी का भला हो।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल आकाश पाल, ब्लॉक प्रमुख नवदीप यादव, वालेचरण बाल्मीकि, शुभम बाल्मीकि, डॉ राजीव, नीरज चंद्रा, अशोक प्रजापति, परशुराम सैनी, सुदेश, दीपक, रंजीत, अजय, मंजीत, शेखर, चरण, रवि, तेजपाल बाल्मीकि, नरेश बाल्मीकि, इंद्रपाल, उदयपाल सिंह, खेमपाल सिंह, उमेश बाल्मीकि सहित बाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

टीएमयू में शरद पूर्णिमा पर आचार्यश्री विद्यासागर के अवतरण दिवस पर पूजा

आचार्य श्री 108 समयसागर जी महाराज और गणिनी प्रमुख श्री 105 ज्ञानमती माताजी का भी शरद पूर्णिमा को हुआ जन्म

मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के जिनालय में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस पर विधि-विधान से पूजा अर्चना हुई। ब्रह्मचारिणी डॉ. कल्पना जैन के सानिध्य में अभिषेक और शांतिधारा हुई। उल्लेखनीय है, आचार्य श्री 108 समयसागर जी महाराज और गणिनी प्रमुख श्री 105 ज्ञानमती माताजी का जन्म भी शरद पूर्णिमा को हुआ था। आचार्य श्री विद्यासागर जी के संग-संग आचार्य श्री समयसागर जी महाराज और गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माताजी की भी जिनालय परिवार की ओर से आरती की गई। टीएमयू के ग्रुप वाइस चेयरमैन श्री मनीष जैन ने अभिषेक और शांतिधारा की। भक्तामर दीप विधान और नवकार मंत्र का पाठ भी सामूहिक रूप से किया गया। इस अवसर पर मेडिकल के डीन एकेडमिक्स प्रो. एसके जैन, श्री धार्मिक जैन आदि के संग-संग श्रावक-श्राविकाएं भी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय पुजारी परिषद ने श्री परशुराम गंगा मैया की भव्य महाआरती

मुरादाबाद।

राष्ट्रीय पुजारी परिषद द्वारा शरद पूर्णिमा एवं महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर श्री परशुराम गंगा मैय्या की भव्य महाआरती एवं सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ एवं महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र का पूजन का आयोजन प्राचीन शिव राम गंगा मन्दिर घाट अटल घाट निकट कटघर रेलवे स्टेशन मुरादाबाद पर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय पुजारी परिषद के संस्थापक श्याम कृष्ण रस्तोगी ने कहा कि मां गंगा और उसकी सहायक नदियों के के प्रति हिंदू समाज की गहरी आस्था और श्रद्धा है परंतु सरकार और समाज के कुछ लोग इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है पर सफाई कहां हो रही है दिखाई नहीं देता सभी नदियों में सैकड़ो गंदे नाले मिल रहे हैं सरकार में बैठे अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहे । नदियों में रात दिन अवैध खनन हो रहा है और मुरादाबाद में बह रही श्री परशुराम गंगा में तो ऐसा लगता है कि वह केवल भैंसों के लिए ही रह रही है सुबह से लेकर शाम तक भैंसें ही भैंसें दिखाई देती है। राष्ट्रीय पुजारी परिषद मांग करता है कि रामगंगा में जानवरों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए और जो गन्दे नाले मिल रहे हैं उन्हें तुरंत बंद किया जाए । कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर संत महामंडलेश्वर संजय नंद गिरि जी महाराज आचार्य कामेश्वर मिश्रा पंडित तेज नारायण मिश्रा पुजारी महेंद्र पंडित विनोद शर्मा, श्याम शुक्ला नितिन दुबे सतोष गुप्ता सतीश अग्रवाल अंकुर अग्रवाल विनोद रस्तोगी शम्मी रस्तोगी शलभ गुप्ता राकेश अत्रि आराधना अग्रवाल वंदना शर्मा सुमन रोहिल्ला गीता पांडे शकुंतला शर्मा आदि में भाग लिया ।

प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल का छठवां स्थापना दिवस संपन्न

बहराइच।

प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल का छठवां स्थापना दिवस एवं द्विवार्षिक स्मारिका विमोचन समारोह एस. पलक बैंक्वेट हॉल, बहराइच में बड़े उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ।इस अवसर पर मानवाधिकारों की सुरक्षा, जेल सुधार, सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के मुद्दों पर सारगर्भित विचार-विमर्श हुआ।इस कार्यक्रम का शुभारंभ केशव राम शास्त्री द्वारा सरस्वती वंदना से किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अबुल लैस 'एडवोकेट' ने की। जबकि मुख्य अतिथि विराट शिरोमणि (अपर जिला जज पंचम व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच) तथा विशिष्ट अतिथि राम जी बाजपेई अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन बहराइच रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अबुल लैस 'एडवोकेट' ने जेलों में बंद कैदियों की आत्महत्या की घटनाओं और मानवाधिकार संरक्षण की आवश्यकता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में न्याय

तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विराट शिरोमणि ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर नागरिक को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी समझ होनी चाहिए।

विशिष्ट अतिथि राम जी बाजपेई ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता दोनों मिलकर ही सशक्त राष्ट्र की नींव रख सकते हैं। राष्ट्रीय महासचिव डॉ. विपिन गुप्ता ने देशभर में संगठन की गतिविधियों, मानवाधिकार जनजागरूकता अभियानों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सदन त्रिपाठी 'एडवोकेट' राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ÷मानवाधिकारों की रक्षा ही राष्ट्र की सच्ची सेवा है। इसके अलावा रामसागर राव 'एडवोकेट' राष्ट्रीय संगठन सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन समाज के हर वर्ग तक न्याय और अधिकार की जागरूकता पहुँचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र पाल श्रीवास्तव 'एडवोकेट', छन्नू लाल शुक्ला 'एडवोकेट', रमेश गौतम 'एडवोकेट', हसन इश्तियाक, शाह आलम खान मंडल प्रमुख प्रशासनिक संरक्षण, मो इब्राहीम एडवोकेट मंडल उप प्रमुख प्रशासनिक संरक्षण, अमित खरे 'एडवोकेट' जिला अध्यक्ष, परवेज़ अहमद प्रिंस एवं विजय सैनी रुद्रपुर उत्तराखण्ड ने भी संबोधित किया।

सभी वक्ताओं ने संगठन की मानवाधिकार सुरक्षा के क्षेत्र में भूमिका की सराहना करते हुए समाज में समानता, एकता और मानवता के प्रसार का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन सरदार सर्वजीत सिंह ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय, प्रदेशीय, मंडलीय एवं जनपदीय पदाधिकारीगण, अधिवक्ता, समाजसेवी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। अंत में सभी ने संगठन के मूल मंत्र ÷मानव अधिकार जन रक्षा द्वारा के प्रति अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता दोहराई।

असिता खेलो इण्डिया की एक दिवसीय योगासन प्रतियोगिता सम्पन्न

जौनपुर।

खेल से ही पहचान है स्लोगन के साथ असिता खेलो इण्डिया का भव्य आयोजन सम्पन्न हो गया जहां मंचासीन अतिथियों ने अपनी श्रेणी में अव्वल आये बच्चों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नगर के टीडी इण्टर कालेज के सभागार में आयोजित प्रतियोगिता जौनपुर योगासना स्पोर्टस एसोसिएशन के बैनर तले हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरीश चन्द्र यादव राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार एवं विशिष्ट अतिथि सदर विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, जफराबाद के पूर्व विधायक डा. हरेन्द्र प्रताप सिंह, मछलीशहर भाजपा जिलाध्यक्ष डा. अजय सिंह, रोहित कौशिक सचिव

उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, डा. आलोक यादव हड्डी रोग विशेषज्ञ, डा. अंजना सिंह प्रदेश अध्यक्ष हिन्दू भगवा वाहिनी रहे जिन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। प्रतियोगिता में दर्जन भर से अधिक विद्यालयों के सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया जहां 5 बच्चों का ग्रुप बनाकर योग कराया गया। एक श्रेणी में 18 वर्ष से कम एवं दूसरे श्रेणी में 18 वर्ष से अधिक के बच्चों ने प्रतिभाग किया जहां पारम्परिक (ट्रेडिशनल) योगासन एवं कलात्मक एकल (आर्टिस्टिक सिंगल) योगासन हुआ। इस अवसर पर सुरभि यादव, मनुश्री गुप्ता, आशीष पाण्डेय, सूर्यांश प्रकाश सिंह, प्रणिता सेठ, दीपशिखा जी, शिवम सिंह, प्रियंका सिंह, डा. प्रमोद यादव, राहुल प्रजापति, स्वतंत्र मौर्य, उदय सिंह सहित तमाम गणमान्य

लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर आये लोगों के प्रति धन्यवाद टीडी इण्टर काजेज के प्रधानाचार्य डा. सत्य प्रकाश सिंह ने ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन योग गुरू अचल हरीमूर्ति ने किया। अन्त में अंकित सिंह सचिव डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन जौनपुर ने समस्त आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

शिखा पाण्डेय, वंशिका गुप्ता एवं यशिका मौर्या ने पाया प्रथम स्थान

खेल मंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने अव्वल बच्चों को किया पुरस्कृत पारम्परिक (ट्रेडिशनल) योगासन के अण्डर-18 श्रेणी में शिखा पाण्डेय प्रथम, तेजवी जायसवाल द्वितीय, दीप्ति यादव तृतीय, आख्या लाल चतुर्थ, साक्षी जायसवाल पंचम स्थान पर आये। इसी तरह इसी योगासन के 18 प्लस में वंशिका गुप्ता प्रथम, प्रियांशी प्रजापति द्वितीय, प्रीति तृतीय, साक्षी सिंह चतुर्थ, रागिन कुमारी एवं वन्दना कुमारी ने संयुक्त रूप से पंचम स्थान प्राप्त किया।

वहीं कलात्मक एकल (आर्टिस्टिक सिंगल) योगासन में यशिका मौर्या को प्रथम, श्रेया यादव को द्वितीय, आस्था सिंह को तृतीय, भूमि सोनी को चतुर्थ एवं श्रेया सिंह को पंचम स्थान मिला।

इस पर उपस्थित मुख्य अतिथि राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने अव्वल आये समस्त बच्चों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही उपस्थित अन्य अतिथियों ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना किया।

विकसित भारत का रक्षा संकल्प! राजनाथ सिंह ने गिनाए आत्मनिर्भरता के 3 बड़े लक्ष्य

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को विकसित भारत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तीन लक्ष्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को महत्वपूर्ण रक्षा क्षमताओं में उच्च स्तर की आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी और रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक बनना होगा। सिंह नई दिल्ली में रक्षा नवाचार संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत अत्याधुनिक तकनीकी उद्योगों में अग्रणी है, भारत को अग्रणी बनाने के लिए, हमें नई विशिष्ट तकनीकों में प्रगति हासिल करनी होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि भारत इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है, तो भारत रक्षा नवाचार के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बन सकता है। उन्होंने कहा कि आज, जब हम 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमें तीन प्रमुख बातों को ध्यान में रखना होगा- पहला, हमें महत्वपूर्ण रक्षा क्षमताओं में उच्च स्तर की आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। दूसरा, हमें रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक बनना होगा। तीसरा, अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में भारत को आगे बढ़ाने और भारत को अग्रणी बनाने के लिए, हमें कुछ नई विशिष्ट तकनीकों में प्रगति हासिल करनी होगी। अगर हम ये तीन चीजें हासिल कर लेते हैं, तो हम न केवल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाएंगे, बल्कि रक्षा नवाचार के क्षेत्र में भी भारत को दुनिया का अग्रणी देश बना पाएंगे। उन्होंने गैर-संपर्क युद्ध के महत्व में उल्लेखनीय वृद्धि पर जोर दिया और आधुनिक युग में युद्ध की तकनीक-उन्मुख प्रकृति पर प्रकाश डाला, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश को न केवल एआई और क्वांटम तकनीक जैसी वर्तमान अत्याधुनिक तकनीकों में महारत हासिल करनी चाहिए, बल्कि भविष्य की उन तकनीकों पर भी विचार करना चाहिए जिनकी वैश्विक स्तर पर अभी खोज होनी बाकी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का युद्ध पूरी तरह से तकनीक-उन्मुख हो गया है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में इसका प्रदर्शन देखा। हमने देखा कि ड्रोन, ड्रोन-रोधी युद्ध और वायु रक्षा प्रणालियों जैसे गैर-संपर्क युद्ध का महत्व काफी बढ़ गया है। परिणामस्वरूप, आपकी चुनौतियाँ और आपकी जिम्मेदारियाँ दोनों बढ़ रही हैं।

हमें न केवल मौजूदा अत्याधुनिक तकनीकों, जैसे एआई, रक्षा में क्वांटम तकनीक आदि में महारत हासिल करनी चाहिए, बल्कि भविष्य की उन तकनीकों पर भी विचार करना चाहिए जिनकी दुनिया ने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। उन्होंने बताया कि 2021-22 में घरेलू स्रोतों से भारत का पूंजी अधिग्रहण लगभग 74,000 करोड़ रुपये था और 2024-25 के अंत तक इसके बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। राजनाथ ने कहा, 2021-22 में घरेलू स्रोतों से हमारा पूंजी अधिग्रहण लगभग 74,000 करोड़ रुपये था, लेकिन 2024-25 के अंत तक घरेलू स्रोतों से पूंजी अधिग्रहण बढ़कर लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

दिवाली-छठ पर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, देश भर में चलेंगी 12000 ट्रेनें

नई दिल्ली।

केंद्रीय कैबिनेट ने 24634 करोड़ की चार रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी, 894 किलोमीटर बढ़ेगा रेल नेटवर्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले रेल यात्रियों का ध्यान रखते हुए सरकार ने 12000 ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है।

रेलवे दिवाली-छठ जैसे त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए देश भर में 1200 स्पेशल दिवाली-छठ पर 12 हजार ट्रेनें चलाई जा रही है। इसके अलावा आज की कैबिनेट बैठक में चार नई रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। सभी प्रोजेक्ट 3 से 5 साल में पूरे होंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के बारे में ब्रीफिंग करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब हम अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े माल ढुलाई वाले देश बन गए हैं। हम 10 साल पहले जहां थे, उससे हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई है।

चार नई परियोजनाओं का एलान

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में हमने चार नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सात रेलवे कॉरिडोर कुल रेल यातायात का 41फीसदी हिस्सा वहन करते हैं। हमने हाल ही में इन कॉरिडोर को मजबूत करने और और अधिक जोड़ने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। अब, हमने इन कॉरिडोर में न्यूनतम चार लेन और जहाँ संभव हो, छह लेन बनाने का निर्णय लिया है वहीं, इस ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे कई रेलवे परियोजनाएं आ रही हैं, रसद लागत कम हो रही है। जनसंख्या और अर्थव्यवस्था में हमारे जैसे कई देशों ने रेलवे पर ज़ोर दिया है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है और लागत कम करने में भी मदद करता है।

सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश

एसआईआर के तहत हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं का ब्योरा सौपे

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत तैयार अंतिम चुनावी सर्वेक्षण से बाहर रखे गए 3.66 लाख मतदाताओं का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार एसआईआर के तहत बाहर रखे गए मतदाताओं का विवरण 9 अक्टूबर तक देने के लिए कहा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची में जोड़े गए ज्यादातर नाम नए मतदाताओं के हैं और कुछ पुराने मतदाताओं के हैं। बिहार एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक किसी भी बाहर रखे गए मतदाता द्वारा कोई शिकायत या अपील दायर नहीं की गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग बाहर रखे गए मतदाताओं के बारे में जो भी उनके पास है, उसे गुरुवार (9 अक्टूबर) तक पेश करेगा। इसके बाद एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगे की सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी के पास मसौदा मतदाता सूची है और अंतिम सूची भी 30 सितंबर को प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकते हैं। न्यायमूर्ति बागची ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से कहा कि अदालती आदेशों के परिणामस्वरूप चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और पहुंच बढ़ी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि प्रभावित/हटाई गई सूची में शामिल किसी भी मतदाता ने अदालत का रुख नहीं किया है और न ही अपील दायर की है, बल्कि दिल्ली में बैठे राजनेता और गैर-सरकारी संगठन ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार (9 अक्टूबर) को करेगा।

फिजिक्स का नोबेल 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को

स्कॉटहोम।

इस साल फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस को मिला है। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने पर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए मिला है।

क्वांटम टनलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कण किसी बाधा (बैरियर) को कूदकर नहीं बल्कि उसके आर-पार होकर निकल जाता है, जबकि सामान्य फिजिक्स के हिसाब से यह असंभव होना चाहिए। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। लेकिन क्वांटम की दुनिया में छोटे कण कभी-कभी दीवार को पार कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं।

बरेली जाएंगे अखिलेश यादव, टेंशन में पुलिस प्रशासन...विपक्ष के नेताओं की एंट्री पर पहले से बैन

बरेली । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को बरेली के दौरे पर रहेंगे। हालांकि उनके दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से अभी औपचारिक अनुमति नहीं मिली है, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अखिलेश यादव बरेली में पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे जिले की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव हाल में घटी कुछ घटनाओं से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मिलने की भी कोशिश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, बरेली में संगठन से फीडबैक लेकर पार्टी की आगामी रणनीति तय की जाएगी। इसके बाद अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे, जहां वे सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खां से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुलाकात सपा की आंतरिक रणनीति और आगामी चुनावी समीकरणों को नई दिशा दे सकती है। सपा प्रवक्ता नेहा यादव ने बताया कि अखिलेश यादव बुधवार सुबह साढ़े 10 बजे निजी विमान से बरेली पहुंचेंगे, इसके बाद कार से रामपुर के लिए रवाना होंगे और शाम को लखनऊ लौटेंगे।

भाजपा बरेली में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए सपा नेताओं को रोक रही- नेहा यादव

नेहा यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा बरेली में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए सपा नेताओं को रोक रही है। सपा डेलिगेशन को बरेली आने से रोका गया और नेताओं को नजरबंद किया गया, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अखिलेश यादव का यह दौरा संगठन में नई ऊर्जा भरने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करेगा।

वाल्मीकि जयंती : लखनऊ में सीएम योगी बोले-

जो लोग भगवान राम को गाली देते हैं, वे महर्षि का भी अपमान करते हैं

लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश में मंगलवार को वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई गई। योगी सरकार ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सरकार की तरफ से वाल्मीकि से जुड़े सभी मंदिरों और स्थलों पर रामायण पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्ति गीत, भजन और दीप प्रज्वलन समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हाल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि जो लोग भगवान राम को गाली देते हैं, वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। जो लोग भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं, वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भगवान वाल्मीकि के आदर्शों से प्रेरणा लेकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करेंगे।

काफी प्रभावी है वाल्मीकि समाज- सीएम

सीएम ने अपने संबोधन में आगे कहा कि वाल्मीकि समाज बहुत प्रभावी है। वाल्मीकि के नाम पर देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना है। राम मंदिर परिसर में जिन सप्तऋषियों का मंदिर बन चुका है, उसमें एक मंदिर भगवान वाल्मीकि का भी है। यह सभी कार्य डबल इंजन सरकार के समय में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो राम पर विश्वास नहीं करते, रामभक्तों पर गोली चलवाते हैं। उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है। वे वही कार्य करेंगे, जिससे समाज में विघटन हो। सीएम ने अपील की है कि महर्षि वाल्मीकि व भगवान राम के महत्व के बारे में समाज को बताएं। भक्ति भाव जितनी मजबूती से बढ़ेगा, समाज उतना ही सशक्त होगा। क्योंकि, सशक्त समाज ही आत्मनिर्भर बनाता है। वही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान दे पाएगा।

रायबरेली में इंसान नहीं, संविधान की हत्या- भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण- राहुल गांधी

रायबरेली ।

रायबरेली में मॉब लिंचिंग को लेकर राहुल गांधी ने कहा-दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या केवल एक इंसान की नहीं, बल्कि इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। राहुल ने मंगलवार को एक्स पर लिखा- संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है, इंसाफ की जगह डर ने। लेकिन यह देश संविधान से चलेगा, भीड़ की सनक से नहीं। भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है। मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दरअसल, 2 अक्टूबर को

जो रायबरेली में हुआ, वह इस देश के संविधान के प्रति घोर अपराध है। दलित समुदाय के प्रति अपराध है। इस देश और समाज पर कलंक है - खड़गे

हरिओम पासवान की हत्या हुई थी। शुरू में कहा गया था कि युवक ड्रोन चोर था। उसी दिन युवक को पीटने और उसकी लाश के वीडियो भी सामने आए थे। इसके बाद 4 अक्टूबर को एक और वीडियो सामने आया, जिसमें मार खाते हुए युवक राहुल गांधी का नाम लेता है। इस पर भीड़ में से एक शख्स कहता है, यहां सब 'बाबा' वाले हैं। इस मामले में राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साझा लेटर भी लिखा है। जिसे दोनों नेताओं ने एक्स पर शेयर किया। इसमें लिखा है, रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम और क्रूर हत्या की कांग्रेस पार्टी कड़ी से कड़ी निंदा करती है। हमारे देश में एक संविधान है, जो हर इंसान को समानता के भाव से पहचानता है। एक कानून है, जो हर नागरिक की सुरक्षा, उसके अधिकार और उसकी अभिव्यक्ति को समान दर्जा देता है। जो रायबरेली में हुआ, वह इस देश के संविधान के प्रति घोर अपराध है। दलित समुदाय के प्रति अपराध है। इस देश और समाज पर कलंक है। राहुल-खड़गे ने लिखा है, देश में दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर अपराध की संख्या हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। यह हिंसा सबसे अधिक उन्हीं पर होती है, जो वंचित हैं, बहुजन हैं, जिनकी न पर्याप्त हिस्सेदारी है, न प्रतिनिधित्व। चाहे हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो या रायबरेली में हरिओम की हत्या।

चुनाव आयोग में ये बताने की हिम्मत नहीं..., बिहार एसआईआर को लेकर फिर फूटा कांग्रेस का गुस्सा

नई दिल्ली ।कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर फिर से हमला बोलते हुए कहा कि मतदाता सूची से गैर नागरिकों को हटाने के लिए मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की जरूरत पर बल दिया गया, लेकिन चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह देशवासियों को बता सके कि बिहार में कितने गैर नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया में समानता और पारदर्शिता की कमी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी होती कि बिहार में कितने गैर-नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, तो उसकी पोल और भी ज्यादा खुल जाती। जयराम रमेश ने बताया कि बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार से फिर शुरू हो रही है। उन्होंने एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख की तस्वीर भी सोशल मीडिया पोस्ट में साझा की, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में दावा किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने बड़े पैमाने पर लोगों के मताधिकार से वंचित होने की आशंकाओं को कम किया है, लेकिन एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में सटीकता, समानता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। विपक्ष बिहार में एसआईआर प्रक्रिया का तीखा विरोध कर रहा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। हालांकि चुनाव आयोग ने विपक्ष के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने साफ किया कि किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा और किसी भी अपात्र व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।

हिमाचल में बस पर पहाड़ी से मलबा गिरा-18 लोगों की मौत

2 बच्चे बचाए; बिलासपुर में दिनभर हुई बारिश के कारण हादसा, कई अंदर फंसे

बिलासपुर । हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मरोतन से घुमारवीं जा रही संतोषी निजी बस पर शुक्र खड्ड के किनारे बरठीं में भल्लू पुल के पास पहाड़ी से भूस्खलन का मलबा गिर गया। मलबा गिरने से बस की छत उड़कर खड्ड के किनारे जा पहुंची। वहीं सारा मलबा बस पर आ गया। जिससे बस पूरी तरह मलबे की चपेट में आ गई। खबर लिखे जाने तक बस के अंदर से अभी तक 18 शव निकाले गए हैं। दो बच्चियों और एक बच्चे को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें से एक बच्ची की मां दुर्घटना में मारी गई है। बेटियों का प्राथमिक उपचार बरठीं अस्पताल में चला हुआ है।

बस में सवार थे 35 यात्री

बताया जा रहा है कि करीब 35 लोग बस में सवार थे। घटना करीब साढ़े छह बजे हुई है। बस में मरोतन बरठीं, घुमारवीं और बीच के स्टेशनों के लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि बस में 35 के करीब सवारियां थी। चालक और परिचालक की मौत हो चुकी है। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

मुख्यमंत्री ने बस दुर्घटना पर किया गहरा शोक व्यक्त

दुर्घटनाग्रस्त पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री निरंतर जिला प्रशासन के संपर्क में है और उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि घायलों को तुरंत उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया जाए और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री शिमला से पूरे हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

हरियाणा पुलिस के आईजी वाई पूरन कुमार ने खुद को मारी गोली, मौत

चंडीगढ़ । पंजाब व हरियाणा की राजधानी में मंगलवार को बड़ी घटना हुई है। यहां हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। घटना सेक्टर-11 की है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंची है। जानकारी मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी, सीएफएसएल और फॉरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई है जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस के आईजी वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। आईजी वाई पूरन कुमार की कुछ दिन पहले रोहतक के सुनारिया जेल में तैनाती हुई थी। उन्होंने चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित अपनी कोठी में सुसाइड किया है। वाई पूरण कुमार की पत्नी पी अमनीत कुमार विदेश दौरे पर हैं। आईएएस पी अमनीत कुमार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री राव नरबीर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी जापान दौरे पर हैं। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने घर की बेसमेंट में

अपने सिर में गोली मारी है। उनकी एक सप्ताह पहले 29 सितंबर को सुनारिया जेल में ट्रांसफर हुई थी। अभी उन्होंने वहां ज्वाइन नहीं किया। सूत्रों के अनुसार घटना स्थल पर सुसाइड नोट भी मिला है, जिस चंडीगढ़ पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस नहीं कर रही है। वाई पूरन सिंह 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने घर में खुद को गोली मारी है। उधर, घटना के बाद उनके घर पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सेक्टर-16 स्थित जीएमएसएच पहुंचाया है। जानकारी के अनुसार आईजी वाई पूरन कुमार बीते डेढ़ वर्ष से काफी सुर्खियों में रहे थे। उन्हें एडीजीपी रैंक से आईजी रैंक में प्रमोट किया गया था। आईजी वाई पूरन कुमार ने पिछले वर्ष वन ऑफिसर वन हाउस पॉलिसी के तहत शिकायत दी थी और प्रदेश के कई अफसरों की शिकायत की थी। इस वजह से वह सुर्खियों में आए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि कई आईपीएस अफसरों ने एक से ज्यादा सरकारी आवास ले रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने पूर्व डीजीपी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर भी जाति के आधार पर भेदभाव करने की शिकायत आयोग से की थी।

हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा, सोशल मीडिया को लेकर सीजेआई बीआर गवई ने की टिप्पणी

नई दिल्ली । देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है. ऑल इंडिया

जजेज एसोसिएशन मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया के दौर में न्यायपालिका और संवाद के बदलते स्वरूप को लेकर टिप्पणी की. जस्टिस के. विनोद चंद्रन के साथ सुनवाई कर रही बेंच में उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि सोशल मीडिया पर क्या रिपोर्ट हो जाएगा. सुनवाई के दौरान जब एक वकील ने अपनी दलीलें रखीं, तो सीजेआई गवई ने मजाकिया लहजे में कहा कि इन दिनों सोशल मीडिया में हम नहीं जानते कि क्या रिपोर्ट किया जाएगा. आपका मुवक्किल बहुत नाराज होगा. इस पर कोर्टरूम में हल्की मुस्कान फैल गई. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मेरे भाई जस्टिस विनोद चंद्रन कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया के युग में हमें नहीं पता कि इसे कैसे रिपोर्ट किया जाएगा. इसलिए मैंने उनसे कहा कि इसे सिर्फ मेरे कानों तक ही रहने दें. उनकी यह टिप्पणी उस बढ़ते रुझान की झलक है जिसमें अदालत की हर बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती है, कभी-कभी सन्दर्भ से हटकर भी.